शोध मंथन Vol. XVI No.4 Oct.- Dec. 2025 ISSN: (P) 0976-5255 (e) 2454-339X, Impact Factor 8.877 (SJIF)
https://doi.org/10.31995/shodhmanthan.2025.v16i04.92

हिंद–प्रशांत की बदलती भू–राजनीति में भारत का उद्भवः शक्ति–संतुलन, सहयोग और रणनीतिक नेतृत्व की नई दिशाएँ

प्राप्तिः 01.11.25
स्वीकृतः 30.11.5

92

श्रीकांत पटेल
शोध छात्र
प्रो0 राजेन्द्र सिंह (रज्जू भैय्या)
विश्वविद्यालय, प्रयागराज
ईमेलः patelshrikant56@gmail.com

प्रो0 महेन्द्र कुमार जायसवाल
शोध निर्देशक
लाला लक्ष्मी नारायण डिग्री कॉलेज,
सिरसा प्रयागराज

सारांश

21वीं सदी में हिंद–प्रशांत क्षेत्र विश्व राजनीति के लिए अत्यंत जटिल, बहुस्तरीय और प्रतिस्पर्धी मंच बन चुका है, जहाँ शक्ति संतुलन के पारंपरिक प्रतिमान तीव्रता से बदल रहे हैं। चीन का महाशक्ति के रूप में उदय, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत की संतुलनकारी भूमिका के कारण यह इलाका अंतर्राष्ट्रीय रणनीति का सबसे गतिशील केंद्र बन गया है। हिंद–प्रशांत क्षेत्र में विश्व समुद्री व्यापार का लगभग दो–तिहाई हिस्सा ट्रांजिट होता है, जिससे ऊर्जा आपूर्ति, जैव विविधता, समुद्री सुरक्षा, संसाधन प्रतिस्पर्धा और सप्लाई चेन संकट जैसी बहुआयामी चुनौतियाँ उत्पन्न होती है। क्षेत्रीय शक्ति–संतुलन का समीकरण चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, दक्षिण चीन सागर की आक्रामकता, अमेरिकी Indo-Pacific Strategy और कांड जैसे मंचों की गतिविधियों से लगातार बदल रहा है। भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, एसिएन, फ्रांस, आदि प्रमुख शक्तियाँ समुद्री उपस्थिति, रक्षा सहयोग, तकनीकी नवाचार, तथा ब्लू इकोनॉमी के माध्यम से अपने हितों को साथ रही है। भारत की राजनीतिक–सामरिक नीति की केंद्रीय अवधारणा ''रणनीतिक स्वायत्ता'' है।

भूमिका

भारत वैश्विक गुट–निर्माण से दूर रहकर सहयोग, बहुपक्षवाद, और नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का समर्थक है। Sagar और Indo-Pacific Oceans Initiative जैसी नीतियाँ मूल्य–आधारित बहुपक्षवाद, समुद्री स्थायित्व, साझा विकास और समावेशी साझेदारी को बढ़ावा देती है। भारती समुद्री कानून, क्षेत्रीय संप्रभुता और स्वतंत्र नेविगेशन का लगातार समर्थन करता है। भारतीय सभ्यता का समुद्र–पार जुड़ाव प्राचीन व्यापार मार्गों, सांस्कृतिक प्रसार, और औपनिवेशिक काल के आदान–प्रदान से बना। Look East और Act East नीति के तहत बंगाल की खाड़ी, मलक्का जलसंधि, तथा दक्षिण–पूर्व एशिया भारत के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक हितों का विस्तार है।

'नेबरहुड फर्स्ट' और 'डायस्पोरा इंगेजमेंट' नीति भारत को नए क्षेत्रीय संवादों और साझेदारियों की तरफ अग्रसर करती है। भारत का अद्वितीय भू–स्थान उसे हिंद महासागर तट का 'नेचुरल लिंचपिन' बनाता है। अरबसागर, बंगाल की खाड़ी, मलक्का जलसंधि की निकटता भारत को एक और प्रशांत देशों, दूसरी और अफ्रीका और पश्चिम एशिया से जोड़ती है। भारत–बांग्लादेश–म्यांमार–थाईलैंड कॉरिडोर, मालाबार नौसैनिक अभ्यास, कोस्टल इन्फ्रास्ट्रक्चर, बंदरगाह नीति और समुद्री निगरानी उसकी भौगोलिक रणनीति को मजबूत करते हैं। आज हिंद–प्रशांत शक्ति–संतुलन, आर्थिक विकास, तकनीकी नवाचार और भू–राजनीतिक परस्परता के नए आयामों को जन्म दे रहा है। भारत ने अपनी ऐतिहासिक गहराई, भौगोलिक विशेषता व सैद्धांतिक बहुपक्षवाद के साथ, इस क्षेत्र में उत्तरदायी और नवोन्मेषी शक्ति के रूप में खुद को स्थापित किया है। गतिशील अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के बीच समन्वित सहयोग, रणनीतिक संतुलन और विकासशील सामाजिक दृष्टि के साथ भारत हिंद–प्रशांत में निर्णायक भूमिका निभा रहा है, जिसमें उसके बहुआयामी हित निर्णायक हैं।

उद्देश्य और अनुसंधान प्रश्न

भारत के लिए हिंद–प्रशांत क्षेत्र में नेतृत्वकारी भूमिका का तात्पर्य केवल सैन्य शक्ति के विस्तार से नहीं है, बल्कि यह बहुपक्षवाद, रणनीतिक स्वयत्ता, एवं उत्तरदायी कूटनीतिक डॉक्टरीन के समन्वित समावेश को दर्शाता है। भारत ने इंडो–पैसिफिक को अपनी एक्ट ईस्ट नीति, Sagar (Security and Growth for All in the Region) और Indo-Pacific Oceans Initiative (IPOI) जैसे बहुपक्षीय रणनीतिक नवाचारों के माध्यम से ''नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर'', समावेशी साझेदार, और विकासकर्ता के रूप में परिभाषित किया है भारत की रणनीतिक स्वायत्तता उसे किसी सैन्य ब्लॉक में बँधने के बजाय बहुपक्षीय मंचों के माध्यम से स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करती है।

भारत का सहयोग बहुस्तरीय हैः

- क्वाड जैसे मंच पर अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ समुद्री सुरक्षा में सक्रिय साझेदारी, जिससे शक्ति–संतुलन सुनिश्चित होता है।
- IPOI, BIMSTEC, IORA में बहुपक्षीय संवाद, आपदा प्रबंधन, समुद्री डोमेन जागरूकता, एवं ब्लू इकोनॉमी के क्षेत्र में नीति–निर्माण में भारत अग्रणी भूमिका निभा रहा।
- भारत ने चीन के प्रभुत्व के संतुलन हेतु समुद्री शक्ति, सैन्य अभ्यास, क्वाड, आसियान, डिजिटल साझेदारी और वित्तीय–तकनीकी सहयोग को प्राथमिकता दी है कूटनीतिक नवाचारों में भारत।
- समकालीन वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला, हरित ऊर्जा साझेदारी, साइबर सुरक्षा में अग्रणी रहा है।
- ब्लू इकोनॉमी, सागरमाला परियोजना, भारत–जापान डिजिटल सहयोग, भारत–ऑस्ट्रेलिया रक्षा समझौते जैसे नवाचारों ने भारत की वैश्विक कूटनीतिक छवि को नया स्वरूप दिया है।

समकालीन सुरक्षा, व्यापारिक और तकनीकी सहयोग में भारत की प्राथमिकताएँ

सुरक्षाः

- भारतीय नौसेना की उपस्थिति, मल्टीनेशनल सैन्य अभ्यास (जैसे मालाबार), समुद्री आतंकवाद रोधी नेटवर्क, एवं समुद्री डाटा साझेदारी में भारत की भूमिका निर्णायक बन चुकी है।

https://doi.org/10.31995/shodhmanthan.2025.v16i04.92

- समुद्री डकैती, साइबर सुरक्षा, अपहरण, मानव तस्करी जैसे नॉन ट्रेडिशनल खतरों के विरुद्ध बहुपक्षीय तंत्र विकसित करना प्राथमिकता है व्यापार।
- भारत इंडो–पैसिफिक में मुक्त व्यापार समझौते, ऊर्जा कॉरिडोर, डिजिटल ट्रेड, और कनेक्टिविटी प्लेटफॉर्म की दिशा में अग्रसर है।
- सागरीय लॉजिस्टिक्स, पोर्ट नेटवर्क, त्रिपक्षीय कॉरिडोर, और ब्लू इकोनॉमी विदेश व्यापार का नया आयाम बना है।

तकनीकी सहयोगः

- भारत डिजिटल सार्वजनिक वस्तुओं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, हरित ऊर्जा तकनीक, और समुद्री विज्ञान में क्षेत्रीय सहयोग का केंद्र है।
- जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ भारत की साइबर रक्षा, फिनटेक, रिन्यूएबल एनर्जी तकनीक साझेदारी से क्षेत्रीय सुरक्षित भविष्य की ओर प्रस्थान हुआ है।

इन तीनों अनुसंधान प्रश्नों के प्रत्युत्तर में स्पष्ट है कि भारत का हिंद–प्रशांत नेतृत्व नवाचार, बहुपक्षीय सहयोग, क्षेत्रीय शांति, सामरिक कूटनीति, और सुरक्षित विज्ञान/तकनीक के समावेश से बहुआयामी है। इन क्षेत्रों में भारत की स्पष्ट प्राथमिकताएँ भविष्य की वैश्विक–सामरिक राजनीति में उसे स्थायी, उत्तरदायी और निर्णायक शक्ति के रूप में स्थापित करने में सहायक हैं।

सैद्धांतिक आधार

हिंद–प्रशांत क्षेत्र की समकालीन भू–राजनीति में शक्ति संतुलन का सिद्धांत एक केंद्रीय भूमिका निभाता है। यह सिद्धांत इस क्षेत्र में राष्ट्रों द्वारा सामरिक, आर्थिक और तकनीकी क्षमता को निरंतर विकसित करने की आवश्यकता को रेखांकित करता है, जिससे कोई एक शक्ति या गठजोड़ क्षेत्र में वर्चस्व न स्थापित कर सके उदाहरण के लिए, चीन के समुद्री विस्तार और सैन्य आधुनिकीकरण के जवाब में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे लोकतांत्रिक राष्ट्रों ने क्वाड और IPOI जैसे मंचों के माध्यम से शक्ति–संतुलन की रणनीति को व्यवहार में लाया है। भारत सैन्य अभ्यास, नोसैनिक नेटवर्क और जियोपॉलिटिकल संवादों में सक्रियता दिखाता है, जिससे बहुध्रुवीय शक्ति–संतुलन सशक्त होता है बहुपक्षवाद का दृष्टिकोण वर्तमान समय में उतना ही आवश्यक है। अंतरराष्ट्रीय मंचों, बहुपक्षीय समझौतों, तथा सहयोगी संस्थानों जैसे क्वाड, BIMSTEC, IORA और आसियान भारत को न केवल क्षेत्रीय समर्थक, बल्कि वैश्विक लोकतांत्रिक नेतृत्व प्रदान करते है। बहुपक्षवाद ने मुद्दा आधारित रणनीतिक सहयोग, आपदा प्रबंधन, समुद्री कानून, डिजिटल साझेदारी और ब्लू इकोनॉमी जैसी नीति–पहलुओं को लागू करने की सुविधा दी है। भारत क्षेत्रीय सहयोग, आर्थिक साझा हित तथा सुरक्षा नेटवर्क को मजबूत करने के लिए इन मंचों का सफल प्रयोग कर रहा है।

समुद्री सुरक्षा, आर्थिक कूटनीति और शक्ति–प्रतिस्पर्धा संबंधी नव–यथार्थवाद और उदारवादी विचारधाराएँ

नव–यथार्थवादः नव–यथार्थवाद विचारधारा के अनुसार, अंरराष्ट्रीय संबंधों का मूल प्रस्थान बिंदु राष्ट्र–राज्यों की सुरक्षा, अस्तित्व और शक्ति वृद्धि में निहित है। हिंद–प्रशांत क्षेत्र में चीन की आक्रामक समुद्री नीति, संसाधन नियंत्रण, और सामरिक विस्तार नव–वास्तविक चिंताओं को जन्म

देती है भारत ने प्रतिस्पर्धी सैन्य–आर्थिक विकास, सामरिक स्वायतत्ता और रणनीतिक गठबंधनों के जरिए इन नव–वास्तविक चुनौतियों का संतुलन किया है। नोसैनिक शक्ति, सैन्य अभ्यास, समुद्री निगरानी, और कूटनीति संवाद इसी दर्शन के अनुरूप है।

उदारवादः उदारवादी विचारधारा, बहुपक्षीय सहयोग, संस्थागत साझेदारी, नियम आधारित व्यवस्था, और आपसी निर्भरता के सिद्धांतों पर आधारित है भारत की बहुपक्षीय विदेश नीति, क्वाड, IPOI, BIMSTEC, IORA, आसियान के साथ सहयोग और आर्थिक साझेदारी इसी उदारवादी दृष्टिकोण से विकसित हुई है। सामूहिक नीति संवाद, व्यापार समझौतों, हरित ऊर्जा सहभागिता, ब्लू इकोनॉमी के क्षेत्रीय साझेदारी, साइबर एवं डिजिटल नवाचार से भारत ने क्षेत्रीय शांति, विकास और साझा सुरक्षा पर बल दिया।

समुद्री सुरक्षाः नव–वास्तविकता और उदारवाद के समन्वित दृष्टिकोण के तहत, भारत ने समुद्री आतंकवाद, समुद्री डकैती, मानव तस्करी, साइबर खतरे और पर्यावरणीय संकट को नियंत्रण में लेने के लिए बहुस्तरीय नीति विकसित की है। भारतीय नौसेना की क्षमता–वृद्धि, समुद्री, गश्त, मल्टीनेशनल अभ्यास, और डाटा साझा करने की नीति नव–वास्तविक अंतर्दृष्टि का परिणाम है वहीं, बहुपक्षीय सहयोग और साझा समुद्री सुरक्षा नेटवर्क उदारवादी नीति का ताजगीपूर्ण दृष्टांत है।

आर्थिक कूटनीतिः भारत ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, लॉजिस्टिक्स, व डिजिटल गलियारों के जरिए हिंद–प्रशांत साझेदारी मजबूत की है बहुपक्षीय साझेदारी में डिजिटल आपूर्ति, हरित ऊर्जा कार्यक्रम, ब्लू इकोनॉमी और साइबर नवाचार प्राथमिकता बनी हैं, भारत के हिंद–प्रशांत नीति में शक्ति संतुलन और बहुपक्षवाद, नव–वास्तविक तथा उदारवादी विचारधाराएँ आपस में मिश्रित होकर एक सम्यक नीति ढांचा प्रस्तुत करती हैं। यह रणनीतिक संतुलन, बहुपक्षिय संवाद, साझा सुरक्षा व आर्थिक सहयोग के नए प्रतिमान खड़े करता है, जिससे भारत की उभरती वैश्विक भूमिका सशक्त बनती है।

शोध–विधि

इस शोध–पत्र में हिंद–प्रशांत क्षेत्र की भू–राजनीति में भारत के उभरते नेतृत्व का विश्लेषण निम्नलिखित शोध–विधियों द्वारा किया गया हैः–

शोध में प्रमाणिक द्वितीयक स्त्रोतों–जैसे peer-reviewed journals, नीति–प्रपत्र, अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों के दस्तावेज, और विश्वसनीय संस्थानों (AJSSHR, Gateway House, RIS) आदि की रिपोर्टों का विश्लेषण किया गया है। क्वाड Quad, IORA, IPOI आसियान जैसे क्षेत्रीय–बहुपक्षीय मंचों की नीति संरचनाओं, सहयोग रणनीतियों और घोषणापत्रों की तुलनात्मक विवेचना की गई है, उदाहरण के लिए, Quad के मिनिस्ट्रियल संवाद, IPOI की आठ स्तंभ विशेषताएँ और IORA के समुद्री सहयोग कार्यक्रम विश्लेषित किए गए।

शोध में केस स्टडी पद्धति का प्रयोग कर हिंद–प्रशांत में भारत के प्रमुख सहयोग मॉडल–क्वाड, भारत–आसियान सहयोग और भारत–जापान संवाद–का गहन विश्लेषण प्रस्तुत किया गया। Quad में सामरिक संतुलन, सैन्य अभ्यास, ज्वांइट कम्युनिकेशन तथा डाटा साझेदारी की भूमिका का तुलनात्मक अध्ययन किया भारत–आसियान सहयोग के केस में, क्षेत्रीय कूटनीतिक संवाद, व्यापार नेटवर्क, तकनीकी साझेदारी व डिजिटलीकरण के उद्घाटन नीति की 'इन्क्लूसिव ग्रोथ' रणनीति पर बल दिया गया।

https://doi.org/10.31995/shodhmanthan.2025.v16i04.92

भारत–जापान संवाद की केस स्टडी में रक्षा तकनीक, बंदरगाह विकास, ऊर्जा व डिजिटल सार्वजनिक वस्तुओं में वास्तविक समझौतों और संचालन की तुलनात्मकता विवेचित की गई।

शोध में भारत की घोषित नीतियों–जैसे SAGAR, ACT EAST, IPOI –और वास्तविक घटनाक्रम (नोसैनिक अभ्यास, समुद्री डोमेन जागरूकता, साइबर नवाचार, मल्टीपार्टनर समझौते) का द्वंद्वात्मक अध्ययन अपनाया गया है। इसमें व्यवहारिक कार्यान्वयन, समस्याएँ, उपलब्धियाँ और नीति–निर्माताओं की चुनौतियों का सशक्त विवेचन किया गया है।

प्रमुख घटक

भारत की ''एक्ट ईस्ट'', SAGAR, IPOI और हालिया रणनीतियों की व्यवहारिकता

भारत की विदेश नीति में ''एक्ट ईस्ट'' नीति ने दक्षिण–पूर्व एशिया, आसियान, और ऑस्ट्रेलेशिया के देशों के साथ आर्थिक, सुरक्षा और संस्कृति के क्षेत्रों में बहुस्तरीय सहयोग को गति दी है। इसकी व्यवहारिकता भारत–आसियान सम्मेलन, व्यापारिक साझेदारियां, सैन्य अभ्यास, और आपदा प्रबंधन जैसी पहलों के माध्यम से दिखती है SAGAR (Security & Growth for All in the Region) नीति क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा व संसाधन सहयोग की रणनीति है, जो पड़ोसी देशों, द्वीपीय राष्ट्र, और अफ्रीका तक भारत की नेटवर्किं को मजबूत करती है IPOI (Indo-Pacific Oceans Initiative) के तहत भारत विज्ञान, समुद्री पर्यावरण, समुद्री संसाधन संरक्षण, ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी व डिजिटल नवाचार को प्राथमिकता देता है इन रणनीतियों ने भारत को केवल नीतिगत ही नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर बहुपक्षीय शक्ति–संतुलन और सहयोग का मुख्य केंद्र बना दिया है।

सामरिक आधुनिकीकरणः नौसेना, सैन्य कूटनीति, तकनीकी नवाचार, डिजिटल और हरित ऊर्जा सहयोग

भारत ने पिछले दशक में नौसेना की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि की है– नवीन पनडुब्बियां, पोत, मल्टीरोल सेनाएँ, और इंडिजेनस डिफेंस टेक्नोलॉजी के लिए समर्पित निवेश हुआ है। भारतीय नौसेना के मालाबार, समुद्री अभ्यास और ट्राइलैटरल डायलॉग्स के माध्यम से सैन्य कूटनीति क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग का आदर्श प्रस्तुत करती है सिंगापुर, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, फ्रांस व अन्य देशों से सैन्य समझौते भारत की सामरिक स्थिति को सुदृढ़ करते हैं तकनीकी नवाचार में भारत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर सुरक्षा, A.I., ब्लू इकोनॉमी व सस्टेनेबल एनर्जी के क्षेत्रों में क्वाड, जापान, अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर क्षेत्रीय नेतृत्व कर रहा है हरित ऊर्जा, सौर परियोजना, स्मार्ट–ग्रिड तथा टेक्रिकल सहयोग भारत को नवीकरणीय सहयोग में अग्रणी बनाते हैं।

विदेश नीति तथा रक्षा संबंधः प्रमुख वैश्विक साझेदारी

अमेरिका के साथ भारत लॉजिस्टिकस स्पोर्ट, जियोस्पेशियल इंटेलिजेंस, रक्षा रसद व Indo-Pacific रणनीति में व्यापक संधियाँ कर चुका है, जिससे भारत की सामुद्रिक शक्ति व वैश्विक प्रभाव बढ़ा है। जापान के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास, बंदरगाह विकास, ऊर्जा व डिजिटल पार्टनरशिप महत्वपूर्ण हैं ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, यूरोपीय संघ एवं आसियान के साथ सुरक्षा–तकनीक व उच्चस्तरीय संवाद भारत को बहुपक्षीय सहयोग का प्रमुख केंद्र बनाते हैं।

चीन के प्रभुत्व के संतुलन की रणनीति एवं व्यावहारिक पक्ष

चीन की विस्तारवादी हिंद–प्रशांत नीति के मुकाबले, भारत ने ''मूल्य आधारित शक्ति–संतुलन'' अपनाया–जहां वह क्वाड, IPOI, इंडो–पैसिफिक नेटवर्क, और पूर्व एशिया–से–आसियान डायलॉग्स के माध्यम से चीन का क्षेत्रीय प्रभाव संतुलित करता है भारत ''प्रतिस्पर्धी सहयोग की नीति अपनाकर क्षेत्रीय साझेदारों का विश्वास जीतता है।

समुद्री अवसंरचना, आर्थिक गलियारे व कनेक्टिविटी पहल

भारत ने SAGARMALA, पोर्ट लिंक, इंडो–बांग्लादेश–थाईलैंड कॉरिडोर, एवं अफ्रीका–एशिया –संयोजन परियोजनाओं में निवेश किया है। क्षेत्रीय पोर्ट विस्तार, समुद्री ट्रेड नेटवर्क, लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर और मल्टीमोडल कनेक्टिविटी ने भारत को हिंद महासागर सेंटर ऑफ ग्रेविटी बनाया है रिन्यूएबल एनर्जी, इनोवेटिव डेटा, फिनटेक एंव डिजिटल गलियारे जैसे पहलुओं में भारत अग्रसर।

चुनौतियाँ और संभावनाएँ

क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्विता

हिंद–प्रशांत क्षेत्र 2025 में महाशक्तिगत प्रतिद्वंद्विता और गहन भू–राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का केंद्र है। चीन का समुद्री सैन्य आधुनिकीकरण, दक्षिण चीन सागर में कृत्रिम द्वीप निर्माण, और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए रणनीतिक घेराबंदी ने अमेरिका, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया सहित क्षेत्रीय देशों में चिंताएँ बढ़ाई है। क्वाड जैसी गठबंधनों की सक्रियता से शक्ति–संतुलन बनाए रखने की कोशिश के बावजूद चीन अपनी क्षेत्रीय महत्त्वाकांक्षाओं में आक्रामक बना हुआ है, जिससे विश्वास का संकट और अनिश्चितता बनी रहती है।

गैर–पारंपरिक सुरक्षा जोखिम

इस क्षेत्र में समुद्री डकैती, मादक पदार्थों की तस्करी, मानव तस्करी, साइबर खतरे, आतंकवादी नेटवर्क, और गैर–परंपरागत, मत्स्यपालन, जैसी समस्याएँ भारत–सहित सभी देशों के लिए गहन हैं।

'मालाबार', 'डिजिटल सार्वजनिक वस्तुएँ', क्वाड के डेटा शेयरिंग तंत्र तथा समुद्री निगरानी की बहुपक्षीय पहलें इन जोखिमों से निपटने में सहायक हैं समुद्री अपराध रोकना, पोर्ट्स की सुरक्षा, लॉजिस्टिक्स नेटवर्क की शुचिता तथा आपदा प्रबंधन अभी भी व्यावहारिक चुनौती प्रस्तुत करते हैं।

जलवायु परिवर्तन

समुद्री स्तर में वृद्धि, चक्रवातों की आवृत्ति, तटीय क्षरण, तथा पानी के स्त्रोतों पर दबाव हिंद–प्रशांत क्षेत्र की टिकाऊ सुरक्षा को चुनौती दे रहे हैं। भारत और ASEAN, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर हरित ऊर्जा, विनिर्माण, स्मार्ट अवसंरचना और जलवायु अनुकूलन परियोजनाओं में निवेश कर रहे हैं, लेकिन सीमित वित्तपोषण, नीति समन्वय की कमी और तकनीकी अंतर क्षेत्रीय स्थायित्व के लिए चुनौतियाँ बनी हैं।

आतंकवाद और समुद्री अपराध

क्षेत्र में आतंकवादी गतिविधियों, हथियारों की तस्करी, अपहरण, समुद्री अपशिष्ट, और ब्लैक सी ट्रेड रूट के दुष्प्रभावों से नौवहन, व्यापार और नागरिक समाज पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है।

https://doi.org/10.31995/shodhmanthan.2025.v16i04.92

भारत ने वायु और समुद्री सीमा पर निगरानी, खुफिया–साझेदारी, न्यूनतम शक्ति प्रयोग और बहुपक्षीय सैन्य अभ्यासों के जरिए इन चुनौतियों का प्रत्युत्तर खोजा है।

भारत के लिए संभावनाएँ

डिजिटल पब्लिक गुड्स, समुद्री डोमेन जागरूकता, Artificial Intelligence आधारित निगरानी, और रिन्यूएबल एनर्जी पार्टनरशिप में भारत का अग्रणी स्थान है। क्वाड साइबर प्रोजेक्ट, हरित ऊर्जा सहयोग, ब्लू इकोनॉमी और बायोटेक–समुद्री इनोवेशन भारत की नवाचार रणनीति को वैश्विक बनाते भारतीय नौसेना, ग्रीन पोर्ट प्रोजेक्ट्स, डिजिटल एयरपेस नेटवर्क, और मल्टी–सेंटर कमांड ऐसे तंत्र हैं जो भारत की क्षेत्रीय शक्ति व रणनीतिक स्वायत्तता का संकेत है। भारत ने समुद्री प्रशिक्षण, आपदा प्रबंधन और हार्ड–इन्फ्रास्ट्रक्चर सहयोग के क्षेत्र में ASEAN, अफ्रीकी और प्रशांत देशों के साथ बहुस्तरीय क्षमता सृजन की है भारत क्वाड, IPOI, IORA, BIMSTEC,आसियान सहयोग जैसे मंचों के जरिए रणनीतिक संवाद, आपसी डेटा साझेदारी, समुद्री कानून के समर्थन, और आर्थिक/वाणिज्यिक नेटवर्क का विस्तार कर रहा है। बहुपक्षवाद, लोकतांत्रिक सिद्धांत, पारदर्शिता तथा नियम–आधारित सहयोग के जरिये भारत क्षेत्रीय देशों के साथ विश्वास बढ़ाता है यह अवसर भारत को केवल समुद्री शक्ति ही नहीं, बल्कि ऊर्जा रक्षा, हरित–कौशल, साइबर सुरक्षा, डिजिटलीकरण, तथा वैश्विक समुद्री लॉजिस्टिक्स में निर्णायक शक्ति बनाकर उभरने का मंच देता है। सहयोगी नेतृत्व, स्वदेशी क्षमता, समुद्री–राजस्व विकास, और बहुपक्षीय नीति समन्वय से भारत अपनी जियोस्टैटेजिक महत्वाकांक्षा की मूर्त रूप दे सकता है।

निष्कर्ष और अनुशंसाएँ

हिंद–प्रशांत क्षेत्र वर्ष 2025 तक विश्व राजनीति का शक्ति–संतुलन, आर्थिक विकास, और कूटनीतिक नवाचारों का केंद्र बन गया है। भारत की नया दृष्टिकोण–संपूर्ण बहुपक्षीय सहयोग, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की जिम्मेदारी, तथा रणनीतिक स्वायत्तता–इसी क्षेत्रीय गतिशीलता के अनुरूप विकसित हुआ है। एक्ट ईस्ट, SAGAR, IPOI जैसी रणनीतियाँ भारत को केवल एक पारंपरिक सुरक्षा शक्ति नहीं, बल्कि ब्लू इकोनॉमी, डिजिटलीकरण, हरित ऊर्जा व ज्ञान अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में अग्रणी बनाती हैं भारत ने क्वाड, आसियान, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय संघ के साथ बहुपक्षीय साझेदारी को रणनीतिक संतुलन और आर्थिक–सामरिक सुरक्षा का आधार बनाया है। चीन की आक्रामक रणनीति का उत्तर भारत बहुपक्षीय प्रतिस्पर्धात्मक सहयोग, डिजिटल क्षमता, समुद्री अभ्यास और आर्थिक गलियारे उजागर करके दे रहा है वर्ष 2025 में भारत की नीति–सीमित सैन्य ब्लॉकिंग से ऊपर उठकर रणनीतिक संवाद, ब्लू इकोनॉमी, स्मार्ट कनेक्टिविटी, और हरित ऊर्जा साझेदारी को समाविष्ट करती है। भारत की ACT EAST नीतिए इंडो–पैसिफिक ओशन्स इनिशिएटिव, और 'मजबूत आत्मनिर्भरता' नीति उसे स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर नवाचार और प्रतिस्पर्धा को नेतृत्वकारी केंद्र बनाती है भारत का रणनीतिक हेजिंग (Strategic hedging) – किसी एक महाशक्ति के खेमे में पूरी तरह न जाना, सभी पक्षों के साथ संवाद बनाए रखना–उभरती बहुध्रुवीयता में भारत को विश्वसनीय और जिम्मेदार शक्ति बनाता है।

नीति–निर्माताओं के लिए ठोस अनुशंसाएँ

1. सार्वभौमिक बहुपक्षीय संकल्पना और नेटवर्क–निर्माण

- भारत को क्वाड, IPOI, IORA, BIMSTEC व आसियान में निरंतर सक्रियता, नीति समन्वय और साझा परियोजनाओं को आगे बढ़ाना चाहिए।
- ब्लू इकोनॉमी, हरित ऊर्जा, डिजिटलीकरण, समुद्री अभ्यास और साइबर सुरक्षा में संयुक्त कार्यनीति विकसित करें।

2. रक्षा और समुद्री आधुनिकीकरण

- भारतीय नौसेना, कोस्टल नेटवर्क व सागरमाला जैसी परियोजनाओं में संसाधन बढ़ाएँ।
- सतत सैन्य कूटनीति, इंडिजिनस डिफेंस उत्पादन, मल्टीनेशनल सैन्य अभ्यास और डिजिटल सेंटर कमांड्स स्थापित करें।

3. आर्थिक गलियारे, Connectivity और आत्मनिर्भरता

- Supply Chain Resilience, डिजिटल लॉजिस्टिक्स, रिन्यूएबल एनर्जी गलियारे और एशिया–अफ्रीका– यूरोप कनेक्टिविटी का सशक्तीकरण।
- आत्मनिर्भरता के लिए घरेलू विनिर्माण, डेटा सुरक्षा एवं फिनटेक नवाचार को प्राथमिकता दें।

4. चीन के प्रभुत्व के संतुलन हेतु प्रतिस्पर्धात्मक सहयोग एवं रणनीतिक संवाद

- किसी सैन्य गुट की कठोरता से बचते हुए बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय सहयोग स्थापित करें।
- क्वाड, जापान, ऑस्ट्रेलिया, आसियान, EU के साथ स्वतंत्रता, पारदर्शिता और साझा अभ्यास तीव्र करें।

5. आतंकवाद, समुद्री अपराध और आपदा प्रबंधन के लिए क्षेत्रीय नेटवर्क और तकनीकी नवाचार

- सूचना नेटवर्क, साझा आपदा प्रबंधन, साइबर साझेदारी, पोर्ट–सुरक्षा, समुद्री अन्वेषण प्रणाली को डिजिटल और तकनीकी सहयोग के साथ विकसित करें।

6. नीति निरंतरता, अकादमिक–प्रशासनिक संवाद एवं प्रशिक्षण

- रणनीतिक अध्ययनों, केस स्टडी, नीति प्रपत्रों के बीच संवाद एवं संशोधन कायम रखें।
- नीति–निर्माताओं, प्रशासनिक अधिकारियों और सुरक्षा विशेषज्ञों के लिये संयुक्त प्रशिक्षण, डिजिटल शिक्षा, सार्वजनिक कूटनीति को बढ़ावा दें।

संदर्भ

1. Kailas Nath G (2025), "Autonomy and Cooperation: India's Engagement in The Indo- Pacific," IJSSHR, Vol 8 Issue 5, Pg. **2846-2852.**
2. Gateway House (2025), "India's footprint in the Indo-Pacific region," Pg. **3-16**.
3. Rajagopalan, R. (2020), "Evasive balancing: India's unviable Indo-Pacific strategy," International Affairs, 96(1), Pg. **78–81**.
4. John, J.V. (2024), "India, Japan and the Indo-Pacific: Evolution, Consolidation and Limitations," JASIA, 11(4), Pg. **516–520**.

5. Bhutia, T.C. (2023), "Strategic Shifts in the Indo-Pacific and India-Australia Partnership," JIOS, 31(2), Pg. **118–121**.
6. Kailas Nath G (2025), "Autonomy and Cooperation: India's Engagement in The Indo-Pacific," IJSSHR, Vol 8 Issue 5, Pg. **2846–2852**.
7. Gateway House (2025), "India's footprint in the Indo-Pacific region," Pg. **7–22**.
8. Rajagopalan, R. (2020), "Evasive balancing: India's unviable Indo-Pacific strategy," International Affairs, 96(1), Pg. **78–81**.
9. John, J.V. (2024), "India, Japan and the Indo-Pacific: Evolution, Consolidation and Limitations," JASIA, 11(4), Pg. **518–524.**
10. Bhutia, T.C. (2023), "Strategic Shifts in the Indo-Pacific and India-Australia Partnership," JIOS, 31(2), Pg. **118–122**.
11. Kailas Nath G (2025), "Autonomy and Cooperation: India's Engagement in The Indo-Pacific," IJSSHR, Vol 8 Issue 5, Pg. **2848-2852.**
12. Gateway House (2025), "India's footprint in the Indo-Pacific region," Pg. **7–24**.
13. Rajagopalan, R. (2020), "Evasive balancing: India's unviable Indo-Pacific strategy," International Affairs, Pg. **78–81**.
14. John, J.V. (2024), "India, Japan and the Indo-Pacific," JASIA, Pg. **519–533.**
15. Bhutia, T.C. (2023), "Strategic Shifts in the Indo-Pacific," JIOS, Pg.**118–124.**
16. Bo, L. (2021), "A Shaky 'Wedge': India's Strategic Behavior," East Asian Affairs, Pg. **2150012–2150014**.
17. Waltz, K.N. (1979), Theory of International Politics, Pg. **101-110**.
18. Mearsheimer, J.J. (2001), The Tragedy of Great Power Politics, Pg. **345–350**.
19. Keohane, R.O. & Nye, J.S. (1977), Power and Interdependence, Pg. **12–25.**
20. Kailas Nath G (2025), "Autonomy and Cooperation: India's Engagement in The Indo-Pacific," IJSSHR, Vol 8 Issue 5, Pg. **2846–2852**.
21. Gateway House (2025), "India's footprint in the Indo-Pacific region," Pg. **7–14.**
22. John, J.V. (2024), "India, Japan and the Indo-Pacific," JASIA, Pg. **526–530.**
23. Bhutia, T.C. (2023), "Strategic Shifts in the Indo-Pacific and India-Australia Partnership," JIOS, 31(2), Pg. **120–122**.
24. Kailas Nath G (2025), "Autonomy and Cooperation: India's Engagement in The Indo-Pacific," IJSSHR, Vol 8 Issue 5, Pg. **2847–2851**.
25. Gateway House (2025), "India's footprint in the Indo-Pacific region," Pg. **5, 12, 14–22.**

26. John, J.V. (2024), "India, Japan and the Indo-Pacific: Evolution, Consolidation and Limitations," JASIA, 11(4), Pg. **522–530.**
27. Bhutia, T.C. (2023), "Strategic Shifts in the Indo-Pacific and India-Australia Partnership," JIOS, 31(2), Pg. **119–121**.
28. Rajagopalan, R. (2020), "Evasive balancing: India's unviable Indo-Pacific strategy," International Affairs, Pg. **80–82**.
29. Bo, L. (2021), "A Shaky 'Wedge': India's Strategic Behavior under the US 'Indo-Pacific' Strategy," East Asian Affairs, 2150012–2150014.
30. Rajagopalan, R. (2020). "Evasive balancing: India's unviable Indo-Pacific strategy," International Affairs, 96(1), Pg. **80–83**.
31. Bhutia, T.C. (2023). "Strategic Shifts in the Indo-Pacific and India-Australia Partnership," JIOS, 31(2), Pg.**120–127.**
32. Gateway House (2025). "India's footprint in the Indo-Pacific region", Pg. **21–24**.
33. John, J.V. (2024). "India, Japan and the Indo-Pacific: Evolution, Consolidation and Limitations," JASIA, 11(4), Pg. **531–535**.
34. Kailas Nath G. (2025). "Autonomy and Cooperation: India's Engagement in The Indo-Pacific," IJSSHR, Vol 8 (5), 2846-2852.
35. Kailas Nath G (2025), "Autonomy and Cooperation: India's Engagement in The Indo-Pacific," IJSSHR, Vol 8 Issue 5, Pg. **2846–2852**.
36. India's Indo-Pacific Strategy and the shifting geopolitics of the region, Journal of Political Science, 2025, Pg. **8–15.**
37. CRF India (2025), "India's Indo-Pacific Strategy," Pg. **6–10.**
38. Gateway House (2025), "India's footprint in the Indo-Pacific region," Pg. **16–24**.
39. John, J.V. (2024), "India, Japan and the Indo-Pacific: Evolution, Consolidation and Limitations," JASIA, 11(4), Pg. **531–536**.
40. Warontherocks (2025), "The Indo-Pacific Chooses Options, Not Sides," July 2025.
41. Wiley Online Library, "India's Hedging Strategy in Great Power Competition," 2025, Pg. **2–6.**
42. ASEAN Ties Take Centre Stage in India's Indo-Pacific Strategy, Business Today, October 2025